

## भारत के सौर ऊर्जा क्षमता को पुनर्जीविति करना

यह एडटिले 15/12/2022 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "An energy conundrum: On India betting big on solar power" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की सौर ऊर्जा क्षमता और संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

भारत की अपनी आबादी और तेज़ी से बढ़ती अरथव्यवस्था के लिये ऊर्जा प्रावधान बढ़ाने की आवश्यकता एक वकिट चुनौती पेश करती है, जिसे समग्र ऊर्जा मणिकरण में [नवीकरणीय ऊर्जा](#) की हसिसेदारी बढ़ाने हेतु देश के लिये एक वृहत अवसर और आवश्यकता दोनों के रूप में देखा जाता है।

- सौर ऊर्जा (Solar Energy) भारत को स्वच्छ ऊर्जा (Cleaner Energy) उत्पादन प्रोद्योगिकियों के अंगीकरण की ओर ले जा रही है। वर्ष 2010 में 10 मेगावाट (MW) से भी कम क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत ने पछिले एक दशक में उल्लेखनीय सौर ऊर्जा का योग किया है और वर्ष 2022 तक 50 गीगावाट (GW) से अधिक की क्षमता हासलि कर ली है।
- वैश्वकि जलवायु संकट को संबोधित करने की प्रतबिद्धता को आधार बनाते हुए भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाशम ईंधन स्रोतों से अपनी लगभग आधी ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने का संकल्प लिया है और लघु अवधि में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा का कम से कम 60% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का निश्चय किया है।
- इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सौर ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ इसकी वहनीयता एवं पहुँच पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

### सौर ऊर्जा की क्या आवश्यकता है?

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत की ऊर्जा मांग बड़े पैमाने पर ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जाती है। इन जीवाशम संसाधनों की कमी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता पर बल देती है।
  - सौर ऊर्जा की प्रचुरता भारत की स्वच्छ ऊर्जा मांगों को पूरा कर सकती है।
- **आरथकि वकिस:** चूँकि भारत एक वकिसशील अरथव्यवस्था है, इसके औद्योगिक वकिस और कृषि के लिये बजिली की उपयुक्त आवश्यकता है।
  - भारत को बजिली उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं न्यूनतम लागत के साथ ही सुनिश्चित नियमित आपूर्ति की भी आवश्यकता है, जिससे इसके उदयोगों और अरथव्यवस्था को बढ़ावा मिलिए।
- **सामाजिक वकिस:** 'पावर कट' और बजिली की अनुपलब्धता की समस्या (वशिष्ठ रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) अनुपयुक्त मानव वकिस की ओर ले जाती है।
  - ऊर्जा की अधिकांश मांग सब्सिडीयुक्त करिसन तेल से पूरी की जाती है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है।
- **पर्यावरण संबंधी चिन्ह:** भारत की ऊर्जा मांग का एक बड़ा भाग तापीय ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाता है जो वृहत रूप से जीवाशम ईंधन पर निर्भर है।
  - इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। सौर ऊर्जा ऊर्जा संसाधन का एक स्वच्छ रूप है, जो एक बेहतर वकिल्प हो सकता है।

### भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार की प्रमुख योजनाएँ

- [अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन](#) (International Solar Alliance)
- [राष्ट्रीय सौर मिशन](#) (National Solar Mission)
- [क्रिसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान](#) (PM-KUSUM)
- ['वन सन, वन वरलड, वन ग्रांडी'](#) (OSOWOG)

### भारत में सौर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **विद्युत क्षेत्र में अपर्याप्त योगदान:** स्थापति सौर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद देश के विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान उस गति से नहीं बढ़ा है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2019-20 में सौर ऊर्जा ने भारत के 1390 बलियन यूनिट कुल बजिली उत्पादन में केवल 3.6% (50 बलियन यूनिट) का योगदान किया।
  - इसके अलावा, जबकि भारत ने यूटिलिटी-स्केल खंड में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये रकिंगड नमिन टैरफि हासलि किया है, यह अंतमि उपभोक्ताओं के लिये सस्ती बजिली उपलब्ध कराने के रूप में फलति नहीं हुआ है।
  - **उच्च आयात नरिभरता:** भारत की वर्तमान सोलर मॉड्यूल नरिमाण क्षमता ~15 GW परत विश्व तक सीमित है। इसके अलावा, भारत के पास सोलर वेफर्स (solar wafers) और पॉलीसिलिकॉइन इंगोट्स (polysilicon ingots) के लिये कोई नरिमाण क्षमता उपलब्ध नहीं है और मौजूदा तैनाती सतरों पर भी इसे अभी 100% सलिकॉइन वेफर्स और लगभग 80% सेल का आयात करना पड़ता है।
    - आपूरति शृंखला के शस्त्ररीकरण का जोखिम: वशीष रूप से सलिकॉइन वेफर—जो सबसे महँगी कच्ची सामग्री है, भारत में वनिरिमति नहीं होती है। चैकिंवर्तमान में दुनिया का 90% से अधिक सोलर वेफर का वनिरिमाण में चीन में होता है, भारत और चीन के बीच मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव भविष्य में आपूरति शृंखला के शस्त्ररीकरण का कारण बन सकता है।
  - **जगह की कमी:** सौर परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये बहुत अधिक जगह/भूमि की आवश्यकता होती है और भारत में भूमि की उपलब्धता कम है।
    - भूमि के एक छोटे से टुकड़े के लिये सबस्टेशनों के पास स्थिति सोलर सेल्स को अन्य भूमि-आधारित आवश्यकताओं के साथ प्रतसिप्रदधा करनी पड़ सकती है, जिसके परणिमस्वरूप स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष की स्थिति बन सकती है।
  - **सौर अपशिष्ट:** अनुमान है कि विश्व 2050 तक भारत का सौर अपशिष्ट 1.8 मलियन टन तक बढ़ जाएगा। वर्तमान में ई-अपशिष्ट नियम (e-waste rules) सौर सेल नरिमाताओं के लिये अनविार्य नहीं हैं, जो प्रतिवर्ष वृहत मात्रा में सौर अपशिष्ट के उत्पादन का कारण बनता है।
  - **लागत और T&D (परेषण और वत्तिरण) में घाटे:** सौर ऊर्जा को लागत प्रतसिप्रदधात्मकता और ऊर्जा के अन्य स्रोतों के साथ प्रतसिप्रदधा की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।
    - T&D घाटों की लागत लगभग 40% है जो सौर ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादन को अत्यधिक अवयावहारकि बना देती है।

आगे की राह

- **सौर ऊर्जा क्षेत्र में वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव (EPR):** भारत वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव (Extended Producer Responsibility- EPR) के संबंध में उचित दशा-निर्देश वकिसति करने पर वचार कर सकता है, जिसका अर्थ है सौर उत्पादों के पूरे जीवन चक्र के लिये नरिमाताओं को जयाबदेह ठहराना और अपशिष्ट पुनर्व्यवस्था के लिये मानकों की स्थापना करना।
    - यह घरेलू वनिरिमाताओं को एक प्रतिसिपर्दधी लाभ की स्थिति पहुँचा सकता है और अपशिष्ट प्रबंधन तथा आपूरतिपक्ष की बाधाओं को दूर करने में दीर्घकालिक योगदान कर सकता है।
  - **सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता:** 'आत्मनिर्भर भारत' के वज़िन के एक भाग के रूप में भारत को एक मजबूत घरेलू सौर ऊर्जा बाजार वकिसति करना चाहिये। सोलर पीवी वनिरिमाण को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि अप्स्ट्रीम स्टार्ट अप्स कंपनियों को प्रत्यक्ष समर्थन दिया जाए, जहाँ डिजिइन एवं उत्पादन के लिये उन्हें वितीय परोत्साहन दिया जा सकता है।
    - भारत सूक्ष्मजीवी प्रकाश-संश्लेषक एवं श्वसन प्रक्रियाओं (Microbial Photosynthetic and Respiration Processes) से बिजिली पैदा करके जैव सौर कोशिकाओं के उपयोग की दशा में भी आगे कदम बढ़ा सकता है।
  - **स्थानीयकृत सौर ऊर्जा उत्पादन:** मनी-गरड़ी और सामुदायिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन भारत में सौर ऊर्जा की दशा में संकरण को सुविधाजनक बना सकते हैं, जबकि पंचायतों और नगर निकायों द्वारा कार्यान्वयित स्थानीयकृत सौर ऊर्जा उत्पादन एवं उपयोग (Localised Solar Energy Production And Utilisation) वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य भारत (Net-Zero India) के हमारे लक्ष्य की पूरता हेतु आधारशलि का नरिमाण कर सकते हैं।
  - **सौर कूटनीति:** वर्ष 2015 में कांफरेंस ऑफ पार्टीज (COP-21) में भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) नवीश जुटाने, क्षमता नरिमाण, आपूरत शृंखला के विधिकरण और वैश्वकि कल्याण के लिये सौर ऊर्जा को समर्थन जैसे विषयों पर दुनिया के देशों को एक साथ लाने का एक मंच बन सकता है।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में सौर ऊरजा उत्पादन से संबद्ध चुनौतियों की विवरण कीजिये और विचार कीजिये कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्वकि ऊरजा सुरक्षा में किसी प्रकार योगदान दे सकता है।

## **यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)**

????????????????????????????????????????????

पर. इंडियन रनियूर्बल एनरजी डेवलपमेंट ईज़ॅसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में, नमिनलखिति में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (वरष 2015)

1. यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है।
  2. यह एक गैर-बैंकगी वत्तियीय कंपनी है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1
  - (B) केवल 2
  - (C) 1 और 2 दोनों
  - (D) न तो 1 और न ही 2

## ?????????????

पर. "सतत् विकास लक्षणों (SDG) को प्राप्त करने के लिए सश्ती, भरोसेमंद, टकिाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच अनविार्य है।" इस संबंध में भारत में हुई प्रगतिपूर्ण टपिक्पणी करें। (वर्ष 2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/revitalising-india-s-solar-energy-capacity>

